भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3217

28 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में

3217 श्री नीरज डांगीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2019 के अपने घोषणापत्र में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में सब्जियों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसानों को उनका उचित हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किसानों को उनका हिस्सा दिलाने में क्यों विफल रही है; और

(ग) सरकार किसानों के लिए वर्ष 2019 के अपने घोषणापत्र के वादे को कब तक पूरा करेगी और किसानों की आय कब तक दोगुनी होगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इन सिफारिशों के अनुसार प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए 23 जनवरी, 2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय का भी गठन किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति (डीएफआई) कृषि को एक मूल्य आधारित उद्यम के रूप में मान्यता देती है और इसने विकास के सात प्रमुख स्रोतों अर्थात फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन लागत में बचत; फसल गहनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण; किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार; और कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों की ओर की बदलाव की पहचान की है । डीएफआई समिति की सिफारिशों पर कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी योजनाएं/कार्यक्रम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के अनुरूप हैं।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों का कल्याण करने के लिए हैं। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)

5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)

6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)

8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)

12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)

16. वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)

17. कृषि वानिकी

18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)

20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)

21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)

22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)

23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तेल पाम

25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

27. डिजिटल कृषि मिशन

28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कन्वर्जेंस से अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ा ली है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।

इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में 6,426 रुपए से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10,218 रुपए हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय संबंधी एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधि में औसत एमपीसीई (रुपये)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर	83.9	69.7

*****